सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 166 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार 23 जुलाई, 2026
मूल्य ₹ 3/-

विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकश किया जा सकता है।
-हेलेन केलर

रोहित ने वनडे रैंकिंग में लगाई... 7 | राजस्थान की राजनीति में दिख... 3 | सपा प्रमुख ने दिल्ली पुलिस की... 2

छात्र आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग

शिक्षा पर संग्राम सत्ता से सीधी टक्कर

» न सरकार झुकने को तैयार न विपक्ष पीछे हटने को राजी

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जब देश में किताबों से ज्यादा बहस राजनीति पर होने लगे जब छात्रों के सवाल सत्ता और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएं तब समझ लीजिए कि मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं रहा। देश इस वक्त ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है।

कैंपस का गुस्सा अब संसद की दीवारों से टकरा रहा है और छात्र आंदोलन धीरे-धीरे भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार है जो अपने फैसलों और अपने मंत्रियों के बचाव में मजबूती से खड़ी है। दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने इस मुद्दे को सीधे जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया है। आरोप प्रत्यारोप प्रदर्शन गिरफ्तारी नारे और राजनीतिक बयान हर नया दिन इस टकराव को और तीखा बना रहा है। शिक्षा का मुद्दा अब केवल विश्वविद्यालयों का मुद्दा नहीं रह गया यह राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ बैठा है।

कौन चुका रहा है असली कीमत

सवाल यह भी है कि आखिर इस लड़ाई की असली कीमत कौन चुका रहा है? सत्ता और विपक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में हैं, लेकिन बीच में खड़ा छात्र आज भी उसी जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके लिए यह पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। संसद में शब्दों की लड़ाई जारी है, सड़कों पर नारों की गूंज है और देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह गतिरोध किसी समाधान तक पहुंचेगा या फिर और गहराएगा। हर राजनीतिक संघर्ष का एक ऐसा क्षण आता है जब पीछे हटना दोनों पक्षों को कमजोरी लगता है। शिक्षा का यह विवाद भी शायद उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। सरकार के लिए यह अधिकार और निर्णय की विश्वसनीयता का सवाल बन गया है जबकि विपक्ष इसे जवाबदेही और राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बनाकर पेश कर रहा है। ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि क्या छात्रों के मूल मुद्दे इस शोर के बीच सुने भी जाएंगे।

क्यों हो रहा है पेपर लीक

आशुतोष सांका ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम में नाकाबिल लोग बैठे हैं। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी जब तक दोषियों के मन में डर पैदा नहीं होगा और जब तक सिस्टम को इस तरह मजबूत नहीं किया जाएगा कि पेपर लीक की गुंजाइश ही न रहे तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक संगठित गिरोह के जरिए होता है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग शामिल होते हैं और आर्थिक लाभ पहुंचता है। इसलिए केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने पीएम के एक्स पोस्ट पर कहा है कि आपने चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात की है जबकि हमारी लड़ाई यह है कि चोट लग ही क्यों

रही है। उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। देश में कई बड़े मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए लेकिन मूल समस्या खत्म नहीं हुई क्योंकि सरकार ने मूल कारणों और व्यवस्था से जुड़ी खामियों को दूर नहीं किया। रांका ने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं की जड़ अक्षमता और भ्रष्टाचार है जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय तक जाती है।

व्यवस्था में बदलाव जरूरी : सीजेपी

नीट यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की घोषणा की। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद दोषियों को क्या सजा दी जाएगी यह एक अलग बात है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक ही क्यों रहे हैं?

उन्होंने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

राहुल के खुलासों से बढ़ी सरकार की बौखलाहट : जयराम रमेश

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खुलासों से सरकार की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से देर शाम आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के सीधे खुलासों के जवाब में आई है। यह

इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। जेपी नड्डा को इस बचकानी उंगली उठाने की राजनीति से आगे बढ़कर पहले मंत्री प्रधान और प्रधानमंत्री की अभूतपूर्व विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए।

एनटीए है जड़

एनटीए की स्थापना वर्तमान सरकार ने विशेष रूप से परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए की थी। सरकार ने जानबूझकर परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण किया उसे एनटीए के माध्यम से संचालित किया और विश्वविद्यालयों व राज्यों पर इसे अपनाने का दबाव बनाया। पहले से मौजूद व्यवस्था को खत्म करके एनटीए को खड़ा किया गया। इसके बाद एनटीए लगातार पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई। उन्होंने कहा कि एनटीए की स्थापना के बाद से अब तक इसके कार्यकाल में कम-से-कम 9 बार पेपर लीक हुए हैं। इनमें 24 की वे घटनाएं भी शामिल हैं जब अनियमितताओं के कारण एनटीए को कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने दुकराया बातचीत का प्रस्ताव

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन सीजेपी के नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार के सत्रों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की मुहिम से जुड़े युवा एकजुट होकर भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

भाजपा के कार्यकर्ता पत्थर फेंककर कर रहे सीजेपी को बदनाम : दिपके

धर्म, जाति, दल और विचारधारा के मुद्दे पीछे हट गए और लगभग पूरा देश सीजेपी की मुहिम से जुड़ता दिख रहा है। अभिजीत दिपके ने गुरुवार को आरोप लगाया कि छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन को जानबूझकर बाधित करने के लिए बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए दिपके ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन एक महीने से बिना किसी ऐसी घटना के चल रहा था, लेकिन प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बाद स्थिति बदल गई।

संबंधित खबरें पेज 8 पर भी

सपा प्रमुख ने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव बोले, पुलिसकर्मी ने मेरा कुर्ता फाड़ने की कोशिश की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली पुलिस पर तीखा प्रहार किया है। सप प्रमुख ने प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करते समय दिल्ली पुलिस पर उनका कुर्ता फाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस की ट्रेनिंग में कहां से आ गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मेरा कुर्ता मजबूत था, गांधी आश्रम का बना था इसलिए वो फटा नहीं, लेकिन, वो उस पुलिसवाले को पहचानते हैं।

अखिलेश यादव ने संसद में पत्रकारों से हुई बातचीत में ये बात कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे कपड़े पकड़ रहे थे पुलिस वाले, बताईए ट्रेनिंग किसने दी आपको कि आप कपड़े फाड़ देंगे, मैंने उसे खुद देखा और कहा कि भाई तू कुर्ता क्यों फाड़ रहा है पुलिस वाले? मैं उसकी शक्ल पहचान गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो भाग गया, अगर उसे खड़ा कर दो तो मैं पहचान लूंगा।

बता दें कि मंगलवार को छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, राहुल गांधी के आह्वान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी थोड़ी देर बात अपने समर्थकों के साथ वहां पहुँच गए, जिसके बाद पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मी पीएम आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी जबरन उठाकर ले गई। विपक्षी दलों के इतने बड़े नेताओं के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस के रवैया पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे सामने अगर उस पुलिस वाले को खड़ा कर दो, तो मैं अभी बता सकता हूं कि कुर्ता किस पुलिस वाले ने पकड़ा था। इसकी तो तस्वीरें हैं, वीडियो है।.. अगर मेरा कुर्ता मजबूत नहीं होता और वो गांधी आश्रम का कुर्ता नहीं होता, तो दिल्ली की पुलिस मेरा कुर्ता फाड़ देती। मेरी सदरी भी मजबूत थी, वो बच गई सदरी। उन्होंने कहा कि पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी, ये ट्रेनिंग किसने दी है। आप चोट लग रही मान लीजिए, राहुल गांधी जी को चोट लग गई। सपा सांसदों के साथ क्या व्यवहार हुआ?

जांचा जाए आखिर ये ट्रेनिंग किसने दी

देश में हर स्तर पर पनपा है भ्रष्टाचार : मायावती

सीजेपी के आंदोलन पर बसपा प्रमुख ने भाजपा को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना तीखा प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने बिना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए संकेतो में उनके धरने पर प्रतिक्रिया दी है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जन्तर मन्तर में पिछले कई दिनों से, ख़ासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपरलीक व अन्य गड़बडियों के दुष्परिणामों से छात्र-छात्राओं व उनके परिवार के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर जारी अनिश्चितकालीन आन्दोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में जबरदस्त हंगामा बरपा है और अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इससे दिल्ली में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने लिखा कि वैसे चाहे पूरे देश में अयोध्या श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा चोरी/ग़बन आदि का गर्म मामला हो या फिर आल-इण्डिया व राज्यों की परीक्षाओं आदि में पेपरलीक का मुद्दा हो, यह सभी मूलत: भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का ही परिणाम है। बसपा चीफ ने लिखा कि इसके साथ ही यह संवैधानिक नैतिकता से भी जुड़ा मामला है, जिसके अभाव में यह देश को दीमक की तरह खाता चला आ रहा है, जबकि संविधान निर्माता परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गुड गवरनेन्स हेतु इस पर ख़ास ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया है। यूपी की पूर्व सीएम ने लिखा कि संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश व जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिये तो यह बेहतर होगा।उन्होंने लिखा कि साथ ही, सीजेपी के व्यापक हो रहे आन्दोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने-अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक में टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित. सरकार व आन्दोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना ही उचित।

युवाओं की आवाज नहीं दबेगी : सचिन पायलट

कांग्रेस नेता बोले- घमंड छोड़िए, शिक्षा व्यवस्था बचाइए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

दौसा। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के भांडारेज मोड़ इंटरचेंज पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही है, जबकि युवाओं के मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। सचिन पायलट ने कहा कि धरना-प्रदर्शन करना और भूख हड़ताल पर बैठना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट शांतिपूर्ण धरना दिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की

मांग करना था। पायलट ने कहा कि धरने में शामिल राहुल गांधी और अन्य सांसद कोई असामाजिक तत्व या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। पायलट ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ मारपीट की गई, कई बच्चों के हाथ-पैर टूट गए और सैकड़ों छात्र अस्पतालों में भर्ती हैं। उनका कहना था कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने चाहिए।

भाजपा के पास छात्रों के भविष्य के लिए कोई विजन नहीं : राबर्ट वाड्रा

» प्रियंका गाधी के पति का सरकार पर बड़ा वार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बिज़नेसमैन व कांग्रेस नेता प्रियंका गाधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 22 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में सरकार की कार्रवाई न करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास छात्रों के लिए कोई विज़न नहीं है और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

एक वीडियो मैसेज में वाड्रा ने कहा कि छात्र और सोनम वांगचुक जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, उसे देखकर मैं हैरान और दुखी हूँ। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं; उनकी चिंताओं को सुनने के बजाय, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस छोड़ी जा रही है। वाड्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर 20 से ज़्यादा छात्रों ने

आत्महत्या कर ली है; जब भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, तो उन्हें देश-विरोधी करार दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनके विरोध-प्रदर्शन रुकेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन ज़ाहिर किया और कहा कि मैं उनके संपर्क में हूँ और हर संभव तरीके से उनकी मदद करूँगा।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया और पेपर लीक की समस्या को सुलझाने या जवाबदेही तय करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दो समस्याएं हैं। एक तो यह कि अलग-अलग परीक्षाओं में लगातार और सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हुए हैं। मंत्री, सेक्रे टरी और एनटीए के प्रमुख वही बने हुए हैं। किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने हमें यह भी नहीं बताया है कि परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है। लोगों का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि NEET अपने आप में संघीय ढांचे के खिलाफ है। एडमिशन उस तरीके से होने चाहिए जिसे राज्य सरकार सही समझे।

उन एडमिशन में केंद्र सरकार के दखल देने का कोई कारण नहीं है। एक मांग NEET को खत्म करने की है और दूसरी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और जवाबदेही तय करने की है, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने से इनकार कर रही है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा

पटना में वामपंथी छात्र संगठन के प्रदर्शन, दोनों सदनों में कांग्रेस-राजद का साथ मिला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन पिछले सत्रों की तरह हंगामेदार रहा। पटना में वामपंथी छात्र संगठन के हंगामे को आज विधान मंडल के दोनों सदनों में कांग्रेस-राजद का साथ मिला। लेकिन, आज भाजपा के पास भी मुद्दा था। कल ही कांग्रेस कार्यालय जाने के दौरान भाजपा नेताओं की जमकर पिटाई हुई थी। लगभग 30 नेता-कार्यकर्ता घायल हुए थे।

बिहार में प्रदर्शन को लेकर पक्ष-विपक्ष की बड़ी भिड़ंत के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कई

» भाजपा और विपक्षी दल आए आमने-सामने

मामलों को लेकर सत्ता और विरोधी दल आमने-सामने थे, तभी भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के कुछ लोग डाकबंगला चौराहे पर उनकी हत्या की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी पर हमला हुआ। किसी तरह जान बचाकर भागे। उन्होंने वामपंथी छात्र संगठन के प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी पर बड़ा बयान दिया। दोनों पक्षों के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दो बजे दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा होगी।

शिक्षा विभाग से जुड़े मामले पर विधायक विमल राजवंशी की ध्यानाकर्षण सूचना का सरकार जवाब देगी। वहीं, सहकारिता विभाग से संबंधित विधायक आलोक कुमार सिंह की ध्यानाकर्षण सूचना पर भी सरकार का वक्तव्य आएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज दिन काफी खास रहने वाला है। आज वामपंथियों के आंदोलन को राजद-कांग्रेस का साथ मिलेगा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा के आसार हैं। विपक्ष छात्रों पर हुए हमले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इधर, लंच ब्रेक सदन में सरकार आज साल 026-27 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी (अनुपूरक बजट) सदन के पटल पर रखेगी।

राजस्थान की राजनीति में दिख रही नई रंगत

हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से पूछा सवाल

कांग्रेस संगठन को बदलने की तैयारी में

» भाजपा बेफिक्र सरकार चलाने में व्यस्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान में राजनीति अपनी रंगत में चल रही है। जहां भाजपा सरकार अपने हिसाब से चल रही है। उधर कांग्रेस में संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की सुगबुहाट हो रही है। डोटासरा दिल्ली की चौखट पर पहुंच गए है। डोटासरा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी तय मानी जा रही है।

जल्द ही नए संगठन का ऐलान होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार को वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ अंतिम दौर की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। उधर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री की ओर से दिए गए जवाब के बाद नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 14-15 से 25-26 के बीच बैंकों ने बड़े कॉरपोरेट्स के 7.75 लाख करोड़ रुपये राइट-ऑफ कर दिए, पर 1,249 बड़े डिफॉल्टर्स के नाम छिपाए जा रहे हैं।

AICC की OBC महिला कमेटी में राजस्थान के दो चेहरे शामिल

दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने संगठन का विस्तार करते हुए ओबीसी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें राजस्थान से दो नेताओं को जगह मिली है। सुचित्रा आर्या को इस विंग का संयोजक नियुक्त किया गया है, जबकि झुंझुनूं के अंकलेश जाखड़ को कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया गया है।

बेनीवाल का बड़ा आरोप-नाम बताने से कतरा रही सरकार

सांसद बेनीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब उन्होंने सदन में इन 1,249 बड़े डिफॉल्टरों और 100 करोड़ रुपये से अधिक का लोन डकारने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की, तो सरकार ने गोपनीयता का हवाला देते हुए नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। बेनीवाल ने पूछा- आखिर सरकार किन कॉरपोरेट घरानों को बचाने की कोशिश कर रही है? जिस बैंक में देश का गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करता है, वहां हजारों करोड़ रुपये डूबने के बावजूद सरकार पारदर्शिता क्यों नहीं बरत रही?

महिलाओं को रिकॉर्ड जगह युवाओं-दलितों पर दांव

सूत्रों की मानें तो इस बार नई पीसीसी टीम में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और युवाओं की हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खासतौर पर, महिलाओं को संगठन में अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। पार्टी आलाकमान इसके जरिए महिला सशक्तीकरण का बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। इसके अलावा, लंबे समय से यह धारणा रही है कि संगठन में कुछ प्रभावशाली समुदायों का ही बोलबाला रहता है। कांग्रेस इस छवि को तोड़ते हुए सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है।

गुटबाजी खत्म करने और संतुलन साधने पर जोर

इस बार आलाकमान की प्राथमिकता यह है कि संगठन में किसी एक गुट का दबदबा न दिखे। सूची को अंतिम रूप देने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की राय भी ली गई है। क्षेत्र, जाति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संतुलित टीम तैयार करने की कोशिश की गई है।

आधे से ज्यादा पदाधिकारियों की छुट्टी तय

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल का दूसरा बड़ा सांगठनिक फेरबदल है। बीते दिनों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर मौजूदा पदाधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। इसमें सामने आया है कि कई पदाधिकारी पदों पर रहने के बावजूद संगठन के स्तर पर निष्क्रिय थे। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए आलाकमान संगठन में जवाबदेही और जमीन पर सक्रियता चाहता है। यही वजह है कि मौजूदा टीम के आधे से ज्यादा पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना लगभग तय माना जा रहा है।

अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए : बेनीवाल

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों, छात्राओं और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने जारी बयान में कहा कि जो सरकार एक ओर महिला आरक्षण, महिलाओं का सम्मान और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, वही सरकार जब अपनी बात रखने आई बेटियों और युवाओं पर पुलिस के जरिए लाठियां बरसाती है, तो उसका दोहरा चरित्र देश के सामने उजागर हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है तथा इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। आरएलपी प्रमुख

ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों का समाधान संवाद, पारदर्शिता और सकारात्मक पहल के जरिए होना चाहिए, न कि दमन और बल प्रयोग के माध्यम से। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में जनता की आवाज दबाने का प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है और इससे सरकार तथा जनता के बीच विश्वास का संकट पैदा होता है। बेनीवाल ने कहा कि जंतर-मंतर से लेकर संसद के बाहर तक हुआ प्रदर्शन देश में व्यवस्था के प्रति बढ़ते जनाक्रोश का प्रतीक है। उनके अनुसार, देश के युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार अपनी नाराजगी और आक्रोश व्यक्त किया है। वह अन्याय और दमन के खिलाफ जनभावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं की यह आवाज भविष्य में व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकती है।

किसान पर सख्ती, कॉरपोरेट पर हो रही मेहरबानी?

हनुमान बेनीवाल ने बैंकिंग व्यवस्था के दोहरे रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि देश में न्याय के दो अलग-अलग पैमाने चल रहे हैं। यदि कोई किसान या युवा चंद हजार या लाख रुपये का लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक उसे तुरंत डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं और उसकी जमीन या संपत्ति की कुर्की की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ, जब बात बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के बट्टे खाते की आती है, तो सरकार और बैंक अचानक नरम रुख अपना लेते हैं। बेनीवाल ने इसे आर्थिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि देश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके खून-पसीने के पैसे से किन-किन बड़े पूंजीपतियों के कर्ज राइट-ऑफ किए गए हैं।

कॉरपोरेट लोन के बट्टे खाते में जाने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ा

उधर संसद के सत्र के दौरान कॉरपोरेट लोन के बट्टे खाते में जाने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया है। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में पूछे गए अपने एक लिखित प्रश्न का जवाब आने के बाद सीधे मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेनीवाल ने सवाल उठाया है कि जब आम आदमी से लेकर किसानों पर बकाया वसूलने के लिए बैंक हर तरह के सख्त कदम उठाते हैं, तो लाखों करोड़ रुपये दबाकर बैठे कॉरपोरेट घरानों के नाम उजागर करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है?

संसद में सरकार का जवाब, सामने आए आंकड़े

लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्वीकार किया कि वर्ष 2014-15 से 25-26 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्र से जुड़े बड़े उधारकर्ताओं के 7.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बट्टे खाते में डाल दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस विशालकाय राशि के मुकाबले बैंकों द्वारा इसी अवधि में मात्र 3.10 लाख करोड़ रुपये की ही वसूली संभव हो सकी है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी माना कि 31 मार्च 26 तक 100 करोड़ या उससे अधिक के बट्टे खाते वाले कुल 1,249 बड़े उधारकर्ता हैं, जिन पर कुल 4.19 लाख करोड़ रुपये की राशि बकाया दर्ज है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

वैज्ञानिकों का मोहभंग होना देश की विकास के लिए संकट

पिछले साल 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़कर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र के नए स्टार्टअप की ओर रुख किया है। वीआरएस लेने वालों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च वीकल मार्क-3 के परियोजना निदेशक विक्टर जोसेफ भी हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ भी अग्निकुल कॉस्मोस नामक स्टार्टअप से जुड़े हैं।

आज कल एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि भारत के वैज्ञानिकों का देश के संस्थानों से मोह भंग हो रहा है। जो एक बहुत गंभीर बात है। इससे देश में अनुसंधान प्रभावित होगा देश की तरक्की बाधित होगी। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी कि इस क्षेत्र में निजी निवेश लाने वाली संस्थाओं को शॉर्ट कट अपनाने से रोका जा सके। निजी संस्थाएं इसरो के वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचने की बजाय स्वयं के बूते ऐसा माहौल बनाएं जहां काम करके नए-नए वैज्ञानिक उस तरह की ऊंचाई हासिल कर सकें जैसे इसरो ने लंबी अवधि में किया है। सार्वजनिक संस्थाओं की कीमत पर निजी संस्थाओं को फलीभूत करने का रास्ता देशहित में नहीं है।

दरअसल अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नीति में सरकार की ओर से बदलाव यह संकेत देता है कि इस अहम संस्थान में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले साल 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़कर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र के नए स्टार्टअप की ओर रुख किया है। वीआरएस लेने वालों में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च वीकल मार्क-3 के परियोजना निदेशक विक्टर जोसेफ भी हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ भी अग्निकुल कॉस्मोस नामक स्टार्टअप से जुड़े हैं। जाहिर है कि अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोलने के फैसले का असर अब दिखने लगा है। करीब 400 स्टार्टअप सक्रिय हो चुके हैं और देश की स्पेस इकोनॉमी 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसरो पिछले कई दशकों से दुनियाभर में अपनी अपूर्व सफलताओं, किफायती मिशनों और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाता रहा है। वैज्ञानिक इस संस्थान को अलविदा करना चाहते हैं, तो इसके कारणों पर विचार करने की जरूरत है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के प्रवेश को ही नहीं, बदलती नीतियों और प्रोत्साहन की कमी को भी इसरो का आकर्षण कम होने की वजह माना जा रहा है। हाल के वर्षों में अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट परियोजनाओं में कमी आई है। क्योंकि, सरकार ने मंत्रालयों को अपनी जरूरत के सैटेलाइट खुद लॉन्च करने के लिए कहा है और मंत्रालयों को अपनी जरूरत का अहसास होने में समय लग रहा है। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि विशेष प्रोत्साहन, परफॉर्मेंस बेस्ट इंसेंटिव और विशेष सैलरी जैसी योजनाओं को वापस लेने से निजी क्षेत्रों के विशेष पैकेज का आकर्षण बढ़ गया है। बहरहाल, ताजा आदेश के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफों या वीआरएस आवेदन पर अब संबंधित केंद्र प्रमुख कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

'छात्रों की गूंज' और बदलता चुनावी विमर्श

जयसिंह रावत

उत्तराखंड की राजनीति पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद, सैन्य गौरव और धार्मिक अस्मिता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन हाल ही में देहरादून में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने राज्य और देश की मुख्यधारा की राजनीति को एक नया वैचारिक मोड़ दे दिया है। दो निरंतर कार्यकालों की सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकम्बेंसी) से जूझ रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों का अंबार था। बेरोजगारी और महंगाई जैसे राष्ट्रव्यापी विषयों से लेकर बद्रीनाथ में दान चोरी के कथित विवाद और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे बेहद संवेदनशील स्थानीय मुद्दों तक, कांग्रेस के तरकश में कई तीर थे। पूरा राजनीतिक अमला और सत्ता पक्ष इस बात के लिए मुस्तैद था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी देहरादून की धरती से इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर तीखे तीर चलाएंगे।

विशेष रूप से सैन्य बाहुल्य प्रदेश होने के नाते भाजपा को पूरा यकीन था कि राहुल गांधी 'अग्निवीर योजना' को लेकर सरकार को घेरेंगे। यही वजह थी कि राज्य सरकार ने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए 17 जुलाई की शाम 5 बजे राहुल के कार्यक्रम से ठीक पहले आनन-फानन में अग्निवीर योजना को लेकर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर डाला और सरकार में 'अग्निवीर प्रकोष्ठ' के गठन जैसी बड़ी घोषणाएं भी कर दीं। सरकार ने विपक्ष के सबसे बड़े हमले की धार को पहले ही कुंद करने की पूरी बिसात बिछा रखी थी। लेकिन देहरादून के मंच पर राहुल गांधी ने न तो अग्निवीर का जिक्र किया और न ही अन्य राजनीतिक विवादों का। राहुल गांधी का पूरा ध्यान केवल और केवल एक मुद्दे पर केंद्रित रहा—'पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर सुनियोजित आघात।' राहुल गांधी का यह रुख किसी राजनीतिक चूक का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी और सुनियोजित दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ने समझ लिया है कि राष्ट्रवाद और सैन्य मुद्दों पर भाजपा को उसकी पिच पर घेरना कई बार आत्मघाती साबित होता है।

अग्निवीर पर बोलते ही बहस 'सेना के मनोबल' बनाम 'राजनीति' पर केंद्रित हो जाती, जिससे मूल मुद्दा भटक जाता। उन्होंने राज्य के अन्य भावनात्मक मुद्दों को छुए बिना अपना पूरा फोकस देश और राज्य के युवाओं की सबसे दुखती रग—'पेपर लीक' पर रखा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस

की भावी रणनीति के केंद्र में अब 'युवा और छात्र' आ चुके हैं। इससे पहले कोटा में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने वर्तमान शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को 'रिजेक्शन सिस्टम' करार दिया था। देहरादून का कार्यक्रम इसी वैचारिक विमर्श का अगला और अधिक परिपक्व पड़ाव था। यह जनसभा युवाओं की आकांक्षाओं, रोजगार, शिक्षा और अवसरों की उपलब्धता पर केंद्रित एक गंभीर संवाद था। उत्तराखंड पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, जैसे यूकेएसएसएससी और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए देश का सबसे कड़ा 'नकल विरोधी कानून' लागू किया और कई मामलों में गिरफ्तारियां भी कीं। सरकार ने इसे अपनी प्रशासनिक इच्छाशक्ति के रूप में पेश किया, लेकिन विपक्ष लगातार इसे इस रूप में प्रचारित करने में सफल रहा है कि व्यवस्था के भीतर बैठे लोग युवाओं के भविष्य के साथ 'अनंत अन्याय' कर रहे हैं। राहुल गांधी इसी सामूहिक हताशा को एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय राजनीति दशकों से जातिगत समीकरणों और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम ने यह साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य की राजनीति में जाति और धर्म के पारंपरिक औजारों के समानांतर रोजगार, शिक्षा और समान अवसर भी उतने ही प्रभावशाली चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं। अब सरकार के सामने असली चुनौती यह होगी कि वह केवल कड़े कानून बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि रोजगार और भर्ती व्यवस्था में सुधार के ऐसे ठोस और दृश्यमान परिणाम प्रस्तुत करे, जिससे युवाओं के बीच खोया हुआ भरोसा बहाल हो सके।

यदि नियुक्तियां समय पर, बिना किसी धांधली के और पारदर्शी तरीके से होती हैं, तो विपक्ष के इस नैरेटिव की हवा अपने आप निकल जाएगी। युवा मतदाता आज किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत बनाने या बिगाड़ने में सबसे निर्णायक कारक बन चुके हैं। वे सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, वे जागरूक हैं और अपनी समस्याओं के राजनीतिकरण को अच्छी तरह समझते हैं। राहुल गांधी के देहरादून दौरे ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब लोकलुभावन और भावनात्मक बहसों के जाल में फंसने के बजाय सीधे उस मोर्चे पर लड़ना चाहती है, जहां सरकार सबसे ज्यादा संवेदनशील है।

क्या विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 2075 में हासिल होगा?

कमलेश पांडे

यदि आप विकसित भारत 2047 का स्वप्न देख रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि यदि भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर, उत्पादकता और रोजगार सृजन की गति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ, तो भारत को विकसित देश बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है। बता दें कि यह कोई आधिकारिक सरकारी अनुमान नहीं है, बल्कि कतिपय अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक आर्थिक विश्लेषण पर आधारित दृष्टिकोण मात्र है, जो सत्य के निकट है या परे, यह भविष्य के गर्भ में है।

हाँ, इतना जरूर है कि इससे विपक्ष को सत्तापक्ष की खिल्ली उड़ाने का एक मौका जरूर मिल गया है। दरअसल, इस संदर्भ में चर्चित अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने भी कहा कि यदि वर्तमान गति ऐसी ही बनी रही, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हासिल करना कठिन हो सकता है। मसलन, सुरजीत भल्ला का आशय यह है कि केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। यदि वर्तमान गति, निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन की चुनौतियाँ बनी रहीं, तो भारत को विकसित देश बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने और उनके जैसे अन्य कई अर्थशास्त्रियों द्वारा उठाई जाने वाली प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं- पहली, विकास दर में कमी- विकसित भारत के लक्ष्य के लिए लंबे समय तक 8-9 प्रतिशत या उससे अधिक वास्तविक GDP वृद्धि की आवश्यकता मानी जाती है, जबकि हाल के वर्षों में वृद्धि इससे कम रहने का अनुमान है। दूसरी, प्रति व्यक्ति आय- विकसित देश बनने का आधार केवल कुल GDP नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी है। यदि जनसंख्या के अनुपात में आय पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ती, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है। तीसरी, रोजगार की चुनौती- आर्थिक वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बनने से आय और उपभोग दोनों प्रभावित होते हैं। चौथी, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) GDP और रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाई है। पांचवीं, मानव पूंजी- शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में अभी भी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है।

छठी, वैश्विक अनिश्चितताएँ- भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाएँ, ऊर्जा कीमतें और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक भी विकास की गति को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह एक आर्थिक आकलन है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। यदि भारत अगले दो दशकों में तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगार सृजन, विनिर्माण विस्तार, बुनियादी ढाँचे में निवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो 2047 का लक्ष्य अधिक यथार्थवादी हो सकता है। इसलिए सुरजीत भल्ला का तर्क मूलत: यह है कि यदि वर्तमान गति और संरचनात्मक चुनौतियाँ नहीं बदलीं, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 से काफी आगे खिसक सकता है।

इसके पीछे प्रमुख कारण बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैं- पहला, विकास दर की चुनौती- विकसित देशों की श्रेणी में पहुँचने के लिए भारत को लंबे समय तक लगभग 7-8 प्रतिशत या उससे अधिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि बनाए रखनी होगी। यदि वृद्धि 6 प्रतिशत के आसपास रहती है, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कम होना- भारत की कुल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बड़ी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय अभी विकसित देशों से काफी कम है। तीसरा, रोजगार और उत्पादकता- उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार और श्रम उत्पादकता में तेज सुधार आवश्यक है। चौथा, विनिर्माण क्षेत्र की धीमी प्रगति- यदि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात अपेक्षित गति से नहीं बढ़ते, तो आय वृद्धि सीमित रह सकती है। पांचवां, शिक्षा और स्वास्थ्य- मानव पूंजी में निवेश पर्याप्त न होने पर दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। छठा, बुनियादी ढाँचा और संस्थागत सुधार- न्यायिक दक्षता, भूमि, श्रम और प्रशासनिक सुधारों की गति भी निर्णायक मानी जाती है। वहीं, दूसरी ओर, 2047 के लक्ष्य के समर्थन में भी मजबूत तर्क हैं क्योंकि भारत में सत्ता प्रतिष्ठान के रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही भाजपा नीत राजग की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए विकसित भारत 2047 एक ड्रीम प्रोजेक्ट है।

चूंकि भारत की आजादी प्राप्ति का सौवाँ वर्ष है, इसलिए सरकार इसे ज्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि वैश्विक षड्यंत्रकारी देश अमेरिका/चीन और उनके पिछलग्गू कट्टर मुस्लिम देश भारत की तरक्की से जल-भुन रहे हैं! नामचीन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ऊँची आर्थिक वृद्धि बनाए रखे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़े, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर दे, तथा राज्यों में सुधारों की गति तेज हो, तो विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य अपेक्षाकृत जल्दी यानी कि 2047 तक या उससे कुछ साल पहले भी हासिल किया जा सकता है। इसलिए 2047 और 2075 को निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अलग-अलग आर्थिक परिदृश्यों के रूप में देखना चाहिए। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दो दशकों में भारत सुधारों, निवेश, उत्पादकता, मानव संसाधन विकास की गति और सुशासन व पारदर्शिता कितनी बढ़ा पाता है।

मनाली और डलहौजी

अगर आप बर्फ और हरियाली का संगम देखना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली और डलहौजी से बेहतर कुछ नहीं। रोहतांग पास की बर्फ और सोलांग वैली की पैराग्लाइडिंग आपके हनीमून में रोमांच भर देगी। डलहौजी की विक्टोरियन शैली की इमारतें और खज्जियार का मैदान (मिनी स्विट्जरलैंड) फोटोग्राफी के शौकीन कपल्स के लिए एक शानदार बैकड्रॉप तैयार करते हैं।

चोपता और औली

उत्तराखंड का चोपता अप्रैल-मई में बुरांश के फूलों से ढक जाता है, जो इसे बेहद रोमांटिक बनाता है। यहां से हिमालय की चोटियों का नजारा और तुंगनाथ मंदिर तक की छोटी ट्रेकिंग आपके सफर को रोमांचक बना देती है। पास ही स्थित औली अपनी ठंडी हवाओं और रोपे-वे के लिए मशहूर है। यह जगह उन कपल्स के लिए स्वर्ग के समान है जो प्रकृति की गोद में एकांत चाहते हैं।

ठंडी और शांत वादियों के लिए इन जगहों का बनाएं प्लान

गर्मी के महीनों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भारी गर्मी लेकर आता है, ऐसे में ठंडी और शांत वादियों का चुनाव आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत में कई ऐसे ऑफ-बीट और क्लासिक हिल स्टेशन्स हैं जहां इस सिजन में मौसम सुहाना रहता है और पर्यटकों की भारी भीड़ से भी बचा जा सकता है। उत्तराखंड का चोपता, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या फिर हिमाचल का स्पीति वैली उन कपल्स के लिए बेहतरीन है जो एडवेंचर और सुकून दोनों चाहते हैं। वहीं दक्षिण में मुन्नार के चाय के बागान और ऊटी की वादियां प्यार के रंगों को और गहरा कर देती हैं। सही प्लानिंग और समय पर बुकिंग के साथ आप इन जगहों पर एक यादगार और बजट-फ्रेंडली सफर तय कर सकते हैं।

मुन्नार और वायनाड

अगर आप दक्षिण भारत की ओर यात्रा करना चाहते हैं, तो केरल के मुन्नार और वायनाड की पहाड़ियां आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं। चाय के बागानों के बीच बने रिसॉर्ट्स और वायनाड के ट्री-हाउस स्टे आपके अनुभव को बहुत रोमांचक बना देंगे। अप्रैल के महीने में यहां की हल्की बारिश और धुंध भरी सुबहें वातावरण को और भी ज्यादा रोमांटिक और खुशनुमा बना देती हैं।

बजट व बुकिंग के टिप्स

अप्रैल-मई पीक सीजन होता है, इसलिए फ्लाइट और होटल्स की बुकिंग कम से कम 30 दिन पहले कर लें। महंगे होटलों के बजाय रजिस्टर्ड होमस्टे का चुनाव करें, जिससे आप स्थानीय संस्कृति को भी करीब से जान पाएंगे और बजट भी संतुलित रहेगा। पैदल चलना और लोकल ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें, इससे आपकी यात्रा और किफायती और यादगार बन जाएगा।

हंसना मना है

इंस्पेक्टर- क्या तुमने भागते हुए कातिल को पकड़ लिया? हवलदार- नहीं सर, पर उसकी उंगलियों के निशान ले आया हूं! इंस्पेक्टर- चलो ठीक है, कहां हैं निशान? हवलदार- सर, मेरे गालों पर!

एक बूढ़ी औरत एटीएम के पास पप्पू से बोली: बेटा मेरा बैलन्स चेक करना! पप्पू ने उसे धक्का दे दिया, बूढ़ी औरत गिर गई! पप्पू : आपका बैलन्स खराब है!

एक लड़का एक गधे के सामने अचानक गिर गया। वहां खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने यह देखकर कहा- अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो? लड़का बोला- जी भाभीजी!

पत्नी: अगर मैं खो गयी तो तुम क्या करोगे? पति: मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी: तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति: जिसको मिले उसकी।

बेटा बाप से- पापा से साढू का रिश्ता क्या होता है, बाप: बेटा जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साढू कहलाते हैं... तभी वहां मम्मी आ गई, बस फिर क्या है तब से मम्मी गुस्से से लाल हैं....और पापा डर के मारे पीले।

कहानी | कौवों की गिनती

एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहां पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नजर एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल कहा कि महाराज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए, तो शहंशाह अकबर से पूछा कि बोलो बीरबल कितने कौवे हैं हमारे राज्य में। बीरबल बोले कि महाराज हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले कि अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो? बीरबल बोले कि हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहां आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा कि अगर कम हुए तो? तब बीरबल बोले कि हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहां गए हों। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रसंशा के पात्र बन गए।

कहानी से सीख: बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए, तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद् हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। लाभ के मौके बार-बार प्राप्त होंगे। विवेक का प्रयोग करें। बेकार बातों में समय नष्ट न करें। निवेश शुभ रहेगा। लाभ में वृद्धि होगी।

वृषभ

कोई बड़ी समस्या से सामना हो सकता है। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। किसी विशेष क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने की इच्छा रहेगी।

मिथुन

व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं।

कर्क

जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें।

सिंह

सभी काम पूर्ण होंगे। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। भाग्य का साथ रहेगा।

कन्या

संचित कोष में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें। संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। झंझटों से दूर रहें।

तुला

विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा। व्यापार मनोनुकूल रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी।

वृश्चिक

प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में कमी रह सकती है। दु:खद समाचार की प्राप्ति संभव है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम में मन नहीं लगेगा।

धनु

कुंआरों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। प्रमाद न करें।

मकर

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। कारोबार में मनोनुकूल लाभ होगा। प्रमाद न करें।

कुम्भ

घर-बाहर सहयोग प्राप्त होगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है। बेरोजगारी दूर होगी। अचानक कहीं से लाभ के आसार नजर आ सकते हैं। कर्ज लेना पड़ सकता है।

मीन

चिंता तथा तनाव रहेंगे। बेवजह कहासुनी हो सकती है। जोखिम न लें। आंखों को चोट व रोग से बचाएं। हल्की हंसी-मजाक किसी से भी न करें।

बॉलीवुड | मन की बात

छात्र आंदोलन के समर्थन में आये सलमान खान

मौजूदा समय में देशभर में नीट पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र और छात्राओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने ेक मिल रहा है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सलमान खान ने आवाज उठाई है। देर रात सलमान ने इस मामले पर ट्वीट कर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और विद्यार्थियों को लेकर अपने दिल की बात कही है। आइए जानते हैं कि मातृभूमि कलाकार ने क्या कहा है-एक तरफ ये चर्चा चल रही थी कि छात्रों के इस आंदोलन को किसी फिल्मी सितारे का साथ नहीं मिल रहा है। शुरुआत में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब धीरे-धीरे सेलेब्स इस मामले को लेकर चिंतित होते हुए नजर आए रहे हैं। बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के तौर पर सलमान खान सबसे पहले आगे आए हैं और उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है-शांतिपूर्वक विद्यार्थियों का जो आंदोलन चल रहा था, उसे वैसे ही चलने देना चाहिए था। ये देखना बेहद दुखद है कि इसने हिंसक रूप ले लिया है। छात्र और उनके परिवार घायल हुए उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका समर्थन किया है। इस आंदोलन को किसी भी तरह से राजनीतिक मत बनाइए, ये बच्चों की लड़ाई है और उनका संघर्ष है, हमारा देश को एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जो मेरे आधार पर होना भी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इस मामले पर छात्राओं का साथ देगी और कोई न कोई हल निकाले। इस तरह से सलमान खान ने इस नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे प्रोस्टेट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे एक गंभीर मुद्दा करार दिया है।

'जन नायकन' हुई रिलीज जश्न में डूबे विजय के फैंस

फिल्म जन नायकन आज 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अपनी मूल रिलीज से करीब सात महीने की देरी से फिल्म ने दस्तक दी है। इस मौके पर थलापति के फैंस किसी उत्सव की तरह जश्न मना रहे हैं और फिल्म का भव्य स्वागत किया है। कई जगह सांस्कृतिक आयोजन किए गए हैं।

तमिलनाडु में बुधवार शाम को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म जन नायकन की थिएटर रिलीज का जश्न मनाया गया। इस दौरान प्रोफेशनल लाइटिंग सिस्टम से चमकीले रंगों के साथ खास डांस शो आयोजित किए गए। चेन्नई में वुडलैंड्स और कैसीनो जैसे थिएटरों में फिल्म के आगमन पर खास सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। विजय का स्वागत करने के लिए रात को आसमान में लेजर बीम छोड़ी गईं और प्रशंसकों ने जोशीले गानों पर झूमकर डांस किया।

अब जब आज गुरुवार को फिल्म रिलीज हो गई है तो सिनेमाघरों में भी खूब रौनक है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें विजय की फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों की खुशी देखते बन रही है। फिल्म जन नायकन बतौर एक्टर विजय की आखिरी फिल्म कही जा रही है। अब वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं और राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को देखने पहुंचे दर्शकों ने जैसे ही स्क्रीन पर अभिनेता को देखा वे क्रेजी हो गए। सामूहिक रूप से नाचने लगे।

फिल्म देखने के लिए बुधवार शाम से ही दर्शक जुटने लगे। रात को बड़ी संख्या में दर्शकों ने फिल्म के स्वागत में डांस करते हुए जश्न मनाया। इस दौरान विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके के झंडे भी फहराए गए। बता दें कि एच. विनोद निर्देशित इस फिल्म में विजय के अलावा बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और प्रकाश राज जैसे सितारे भी हैं।

पीटीआई के मुताबिक, केरल के वायनाड में विजय की जन नायकन देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जमा हुए हैं। सुबह 6 बजे से फिल्म के स्पेशल शो दिखाए जा रहे हैं।

विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान विजय के समर्थन में अपार भीड़ उमड़ी। लोग रैलियों में आए। अब जब एक्टर की फिल्म रिलीज हुई है तो एक बार फिर कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला है। प्रशंसकों का एक वर्ग कार और मोटरसाइकिल पर थलापति की तस्वीरों के पोस्टर और बैनर लेकर समूह में निकला है। यह नाजरा ऐसा लग रहा है, मानो कोई रैली हो।

लरिसा बोनेसी भी हो चुकी हैं कास्टिंग काउच का शिकार

आर्यन खान की रूमर्ड गलफ्रेंड बनकर चर्चा में आईं ब्राजिलियन मूल की एक्ट्रेस लरिसा बोनेसी गो गोवा गॉन और थिक्का जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। वो हाल ही में दुल्हनिया ले आएगी फिल्म में नजर आने वाली हैं। लरिसा 32 साल की हैं, और सालों से बॉलीवुड में नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस बीच वो कई बार कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। सिद्धार्थ कनन से बातचीत में इसका खुलासा करते हुए उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया। लरिसा ने कहा- बॉलीवुड में शुरुआत में मुझे भाषा की वजह से दिक्कत होती थी। मैं 12-13 साल की थी जब ब्राजिल से चाइना शिफ्ट हुई थी, इसके बाद मैं भारत आई। मुझे थोड़ी हिंदी आती थी, लेकिन वो फीलिंग समझ नहीं आती थी। तो कोई क्या जोक मार रहा है, क्या ताना मार रहा है वो समझ नहीं आता था। मैं सोचती रह जाती थी कि वो क्या बोल गए।

कास्टिंग काउच पर बात करते हुए लरिसा थोड़ा हिचकीं लेकिन फिर कबूल किया कि हां मुझे बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। लेकिन मैं अब मैं वापस उस बारे में नहीं सोचना चाहती, वो बहुत सेंसिटिव है। लरिसा ने बताया कि उन इंसीडेंट्स ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वो बोलीं- मैं टूट गई थी, उसके बाद कुछ वक्त तक मैंने काम ढूंढना तक बंद कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे घिन आने लगी थी। मेरे मन में कई सवाल आने लगे थे, जैसे- क्या ये इसलिए है कि मैं यहां से नहीं हूं। क्या मैं ब्राजिल की हूं इसलिए मुझसे इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। लरिसा ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा कि- क्या ये लोग ऐसे सोचते हैं कि ये फिरंगी है तो कुछ भी चलेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म तो चाहिए ना। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो भी लोग हैं इनकी वजह से मैं घर पर नहीं बैठ सकती। मेरी जिंदगी इन सबसे कहीं ज्यादा बेहतर है।

अजब-गजब | भारत का वो अनोखा गांव जहां नहीं चलता भारत का कानून

यहां लोगों को छूने पर लगता है जुर्माना

भारत में हजारों गांव हैं और लगभग हर गांव की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपरा है। कहीं आज भी सदियों पुराने रीति-रिवाज निभाए जाते हैं, तो कहीं ऐसे नियम लागू हैं जिन्हें जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई गांव अपनी अनोखी बोली, धार्मिक मान्यताओं, खानपान और सामाजिक व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी और अनोखे गांवों में गिना जाता है। यहां के नियम-कानून इतने अलग हैं कि पहली बार आने वाला हर पर्यटक हैरान रह जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मलाणा गांव में बाहरी लोगों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।

यहां आने वाले पर्यटकों को गांव की दीवारों, मंदिरों, घरों या किसी भी स्थानीय सामान को छूने की अनुमति नहीं होती। यहां तक की पर्यटकों को गांव के लोगों को भी छूना मना है। गांव के कई स्थानों पर साफ-साफ नोटिस लगे हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहां की किसी भी चीज को छूता है, तो उस पर 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही वजह है कि यहां आने वाले लोग काफी सावधानी बरतते हैं। यहां तक कि अगर किसी पर्यटक को दुकान से कोई सामान खरीदना हो, तो वह सीधे सामान को हाथ नहीं लगाता। ग्राहक पैसे दुकान के बाहर रख देता है

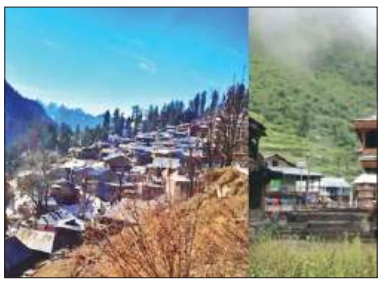

और दुकानदार सामान बाहर जमीन पर रख देता है, जिसे बाद में पर्यटक उठा लेता है। मलाणा गांव की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था है। कहा जाता है कि इस गांव का अपना संविधान है और यहां के लोग सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार गांव को चलाते हैं। गांव में अपनी संसद भी है, जिसमें दो सदन हैं- एक बड़ा और एक छोटा। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं। इनमें से 8 सदस्यों का चुनाव गांव के लोग करते हैं, जबकि 3 सदस्य स्थायी होते हैं, जिनमें कारदार, गुर और पुजारी शामिल हैं। छोटे सदन में गांव के प्रत्येक परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य शामिल होता है। अगर बड़े सदन के किसी सदस्य का निधन हो जाए, तो पूरे सदन का दोबारा गठन किया जाता है। गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अधिकारी और स्थानीय व्यवस्था भी मौजूद है। इस गांव में किसी भी विवाद या महत्वपूर्ण मामले पर पहले संसद में चर्चा होती है। अगर संसद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती, तो अंतिम फैसला जमलू देवता के नाम पर लिया जाता है। गांव के लोग जमलू ऋषि को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनका निर्णय सभी के लिए अंतिम माना जाता है।

मलाणा गांव को लेकर एक बेहद दिलचस्प मान्यता भी है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि जब 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब उसकी सेना के कुछ सैनिक यहीं आकर बस गए थे। इसी वजह से गांव के कुछ लोग खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। हालांकि, इस दावे के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन गांव की बोली में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रीक भाषा से मिलता-जुलता बताया जाता है।कहा जाता है कि सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। यही कारण है कि मलाणा को कई लोग सिकंदर के सैनिकों का गांव भी कहते हैं।

यहां के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो बेहद ही रहस्यमयी है। वो इसे एक पवित्र जबान मानते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये भाषा मलाणा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं।

यहां जवान होते ही मर्द बन जाती हैं महिलाएं, जीती हैं मर्दों की लाइफ, ना करती हैं शादी, ना पैदा होते हैं बच्चे!

उत्तरी अल्बानिया की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों में सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा आज भी कुछ परिवारों में जीवित है। यहां महिलाएं जवान होते ही 'मर्द' बन जाती हैं। उन्हें 'बुर्नेशा' कहा जाता है। यह शब्द अल्बानियाई भाषा में 'पुरुष' का अर्थ रखता है। ये महिलाएं परिवार की मुखिया बनकर सारी जिम्मेदारियां पुरुषों की तरह निभाती हैं लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें आजीवन शादी नहीं करना और बच्चे नहीं पैदा करने की शपथ शामिल है। यह परंपरा 'कनून' नामक प्राचीन जनजातीय कानून पर आधारित है। कनून सदियों से उत्तरी अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में जीवन को नियंत्रित करता रहा है। जब किसी परिवार में कोई पुरुष वारिस नहीं बचता, जैसे कि सभी भाई मर जाते हैं या कोई बेटा नहीं होता, तो परिवार की बेटी बुर्नेशा बनने का फैसला कर सकती है। शपथ लेने के बाद उस महिला को पुरुष का दर्जा मिल जाता है। इस कसम को खाने के बाद महिलाएं पुरुषों वाले कपड़े पहनती है। वो अपना नाम भी पुरुष वाला रख लेती है। समाज उसे पुरुष के रूप में संबोधित करता है। वह संपत्ति खरीद सकती है, विरासत पा सकती है, घर की मुखिया बन सकती है, बाजार जा सकती है और पुरुषों वाली दुनिया में घूम-फिर सकती है। जो आजादी और अधिकार उस समय की आम महिलाओं को नहीं थे, वे सब बुर्नेशा को मिल जाते हैं। लेकिन शपथ बहुत सख्त है। एक बार शपथ लेने के बाद वापसी नहीं की जा सकती। अगर शपथ तोड़ी गई तो सामाजिक बहिष्कार और बदनामी तय है। इसलिए ये महिलाएं जीवन भर कुंवारी रहती हैं और कोई संतान नहीं पैदा करती हैं। पहले के समय में यह परंपरा परिवार की इज्जत और संपत्ति बचाने का एक तरीका थी। युद्ध, बीमारी या दुर्घटना में पुरुषों के मर जाने पर परिवार बिखर जाता था। बुर्नेशा बनकर एक बेटी पूरे परिवार को संभाल लेती थी। समाज भी इसे स्वीकार कर लेता था। आजकल आधुनिकता और कानूनी बदलावों के कारण यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। अल्बानिया में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिल गए हैं। स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसलिए नई पीढ़ी बुर्नेशा बनने का रास्ता चुनने की बजाय सामान्य जीवन जीना पसंद करती है। वर्तमान में सिर्फ मुट्ठी भर बुर्नेशा बची बताई जा रही हैं। इनमें से कई की उम्र 70-80 साल के पार है। वे अब भी पुरुषों वाले कपड़ों में रहती हैं और समाज उन्हें सम्मान देता है। उनकी कहानियां लोकल लोगों और विदेशी पत्रकारों को आकर्षित करती हैं। यह परंपरा जेंडर भूमिकाओं पर एक दिलचस्प नजरिया देती है। एक तरफ जहां आधुनिक दुनिया जेंडर फ्लूइडिटी और ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस कर रही है, वहीं अल्बानिया की यह सदियों पुरानी प्रथा दिखाती है कि जरूरत पड़ने पर समाज जेंडर रोल्स को कैसे बदल सकता है।

कीड़ा टिप्पणी पर मप्र में सियासी विवाद गहराया

» नेता प्रतिपक्ष सिंघार पर मंत्री कैलाश का पलटवार, बोले- मैने ऐसा कहा ही नहीं, करूंगा मानहानि का मुकदमा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश में कीड़ा टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। सरकार के मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी छात्र या युवा के लिए कीड़ा या कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही उन्होंने उमंग सिंघार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात भी कही। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं।

उमंग सिंघार ने जो भी आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने छात्रों के बीच मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। उनका कहना है कि झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को युवाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विवाद बढ़ने पर कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से इस पर व्यवस्था देने की मांग की। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का वीडियो और रिकॉर्ड देखने के बाद स्पष्ट किया कि विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य में कीड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।

उमंग सिंघार ने की माफी की मांग

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्रों को कॉकरोच कहना पूरे युवा वर्ग का अपमान है। उन्होंने कहा कि यदि सदन में छात्रों और युवाओं के संदर्भ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि युवाओं के सम्मान पर चोट है। सिंघार ने कहा कि युवा अपने भविष्य, शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें अपमानित करना और उन पर देश को अस्थिर करने जैसे आरोपों का संकेत देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कैलाश विजयवर्गीय को इस टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने वाले युवाओं का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं।

छात्रों पर हिंसा दुखद, नीट विवाद पर बातचीत करे सरकार : हजारे

» प्रधानमंत्री मोदी को अन्ना हजारे ने लिखा पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जाने-माने एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया है और सरकार से कहा है कि वह जारी आंदोलन को सुलझाने के लिए बातचीत का सकारात्मक रास्ता अपनाए। पिछले एक हफ़्ते में यह दूसरी बार है जब हजारे ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक विवाद को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत का समर्थन किया है। यह पत्र राष्ट्रीय राजधानी में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों के बाद बढ़े तनाव के बीच आया है। भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन और जन-अभियानों के लिए पहचाने जाने वाले हज़ारे ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत की अपील की।

मंत्रियों को जनता की अदालत में आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे संदेश में हज़ारे ने कहा कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से उन्हें दुख हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने की कोशिश करे। हजारे ने अधिकारियों और नागरिकों के बीच बातचीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बातचीत से टकराव को रोका जा सकता है और लोगों की चिंताओं का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की अपील की और ज़ोर दिया कि मतभेदों को सुलझाते समय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ही मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़पें हुईं, जिससे स्थिति को संभालने के तरीके पर चिंताएं पैदा हुईं। कई राजनीतिक नेताओं और जानी-मानी हस्तियों ने इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है और जवाबदेही, बातचीत तथा संयम बरतने की मांग की है।

पंजाब सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा विपक्ष : बलतेज पन्नू

» आप नेता बोले- पेपर लीक पर जवाब दे कांग्रेस और भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। आप के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कांग्रेस और भाजपा पर पंजाब सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दलों को पहले नीट पेपर लीक मामले पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए। बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरीदकोट में सामने आया मामला पेपर लीक का नहीं, बल्कि नकल का था।

उनके अनुसार परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से नकल करते एक अभ्यर्थी को मौके पर ही पकड़ लिया गया था और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर फरीदकोट की घटना को पेपर लीक बताकर अपने शासनकाल के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पन्नू ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में देशभर में 90 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, लेकिन जनता सच्चाई से भली-भांति परिचित है। आप प्रवक्ता ने कांग्रेस और भाजपा से पंजाब सरकार पर निराधार आरोप लगाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जवाब देने की मांग की।

अधिकारियों की नजर में महापौर के आदेश भी हवा में!

» जोन-4 में सड़क पर कूड़े का अंबार, बदबू से लोगों का निकलना हुआ मुश्किल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने हाल ही में सभी नगर निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फील्ड में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी गंदगी, जलभराव या सड़कों पर कूड़ा दिखाई न दे। लेकिन नगर निगम के जोन-4 में इन निर्देशों की खुलेआम अनदेखी होती नजर आ रही है। विकल्प खंड स्थित कठौता झील, पूर्वांचल किंग कोर्ट और रेल विहार कॉलोनी के बीच मुख्य सड़क पर लखनऊ स्वच्छता अभियान नगर निगम द्वारा कूड़ा डाले जाने से पूरे इलाके में बदबू और गंदगी का साम्राज्य फैल गया है।

हालात ऐसे हैं कि लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग रास्ता बदलने को मजबूर हैं, जबकि स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और ऑफिस आने-जाने वालों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी सोनू सिंह का कहना है कि जब खुद नगर निगम ही सड़क को कूड़ाघर बना देगा, तो स्वच्छता अभियान और महापौर के निर्देशों का क्या औचित्य रह जाएगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जोन-4 के जिम्मेदार अधिकारी सुबह फील्ड में निकल रहे हैं या फिर महापौर के आदेश उनके लिए सिर्फ हवा का झोंका बनकर रह गए हैं? जोन-4 के जोनल सेनेटरी ऑफिसर पंकज शुक्ला ने कहा, रोड पर कूड़ा डाला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अभी तत्काल सड़क से कूड़ा हटवाता हूं।

छात्रों पर कार्रवाई की न्यायिक जांच हो : अभय

» इनेलो प्रमुख ने की प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की निंदा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसकी उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कहा कि इनेलो छात्रों की मांगों के समर्थन में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उनके साथ खड़ी रहेगी।

चंडीगढ़ में जारी बयान में चौटाला ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल और कुछ छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। अगर ऐसे आरोप सही हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभय चौटाला ने केंद्र सरकार और संबंधित प्रशासन से मांग की कि पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए।

रोहित ने वनडे रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग

» चौथे स्थान पर पहुंचे, नंबर-1 की दौड़ हुई रोमांचक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स में खेली गई शानदार 138 रन की पारी का इनाम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में मिला है। आईसीसी द्वारा जारी साप्ताहिक रैंकिंग में रोहित 14 रेटिंग अंक की बढ़त के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और अब वह शीर्ष स्थान की दौड़ में मजबूती से शामिल हो गए हैं। फिलहाल न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 802 रेटिंग अंकों के साथ नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं। भारत के शुभमन गिल 801 अंकों के साथ महज एक अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली 767 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर कायम हैं। रोहित शर्मा 758 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से सभी सवालों का जवाब दिया। भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज के बाद इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। जो रूट 249 रन बनाने के बाद चार स्थान की छलांग लगाकर आठवें नंबर पर पहुंच गए। बेन डकेट 11 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर पहुंच गए। जैकब बेथेल पांच स्थान की बढ़त के साथ 64वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे ऊपर अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे स्थान पर हैं। ताजा आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में भारत के तीन बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप-4 में शामिल हैं। इससे साफ है कि भारतीय बल्लेबाजी इस समय विश्व क्रिकेट में सबसे मजबूत इकाइयों में से एक बनी हुई है। खास तौर पर गिल और रोहित की हालिया फॉर्म ने नंबर-1 रैंकिंग की जंग को बेहद रोमांचक बना दिया है।

कुलदीप ने काउंटी क्लब यॉर्कशायर से किया करार

लीड्स। भारतीय टीम के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने बुधवार को इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर से करार किया है। कुलदीप मौजूदा सीजन में टीम के लिए आठ मुकाबले खेलेंगे। कुलदीप पिछले कुछ समय से भारतीय प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। लेकिन अब वह काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे। कुलदीप वनडे कप के पांच मैच खेलने के साथ ही तीन लाल गेंद क्रिकेट के मुकाबले खेलेंगे। यॉर्कशायर क्लब ने कहा, भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को विदेशी खिलाड़ी के तौर पर साइन करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 31 साल के कुलदीप वन डे क के पांच मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे और इसके बाद सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी चार में से तीन मैचों के लिए हेडिंग्ले लौटेंगे। यॉर्कशायर से जुड़ने पर कुलदीप ने कहा, यॉर्कशायर से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इस मौके के लिए आभारी हूं। यॉर्कशायर के गौरवशाली इतिहास वाले क्लब का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सचमुच सम्मान की बात होगी। मुझे हमेशा से इंग्लिश कंडिशन्स में खेलने की चुनौती पसंद रही है और मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैं टीम से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हो गया हूं।

पीएम मोदी ने युवाओं का भविष्य तबाह किया : राहुल

» नीट पेपर लीक पर नेता प्रतिपक्ष का पीएम मोदी पर तीखा पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को तबाह करने का गंभीर आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेता की यह तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवाओं का कल्याण और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनेगा : पीएम मोदी

नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के लगातार विरोध-प्रदर्शन के बीच, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है! जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेपर लीक के मुद्दे पर सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।

शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है और उसे बर्बाद कर दिया गया है

एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है और उसे बर्बाद कर दिया गया है और सरकार पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, आप ही हैं जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा करने और उसे बर्बाद करने की इजाजत दी और उसे बढ़ावा दिया-और इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को बचाया।

मरहम नहीं, पेपर लीक रोकने की व्यवस्था चाहिए : सीजेपी

» पीएम मोदी के एलान पर सीजेपी का पलटवार, कहा- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली । नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की घोषणा की। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने पेपर लीक के मूल कारणों पर सवाल उठाए। आशुतोष रांका ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में नाकाबिल लोग बैठे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के मन में डर पैदा करने की बात कही। रांका ने व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि पेपर लीक की गुंजिश न रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक संगठित गिरोह के जरिये होता है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोग शामिल होते हैं और आर्थिक लाभ उठाते हैं। रांका ने कहा कि केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को बदलना जरूरी है। उन्होंने पीएम के एक्स पोस्ट पर टिप्पणी की कि यह चोट लगने के बाद मरहम लगाने जैसा है। उनकी लड़ाई चोट लगने के कारणों को लेकर है।

आशुतोष रांका ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में कई बड़े मामलों में ऐसे कोर्ट बने, पर मूल समस्या खत्म नहीं हुई। सरकार ने मूल कारणों और व्यवस्था से जुड़ी खामियों को दूर नहीं किया। रांका ने शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं की जड़ अक्षमता और भ्रष्टाचार को बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय तक जाती है। रांका ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामा

» सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन

» सत्ता पक्ष व विपक्ष में वार-पलटवार जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। अभी तक बीते तीन दिन हंगामे के नाम रहे। आज चौथे दिन भी हंगामा जारी है। आज संसद के अंदर और बाहर दोनों ओर नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। पहले संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। फिर सदन में भी नारेबाजी हुई। जिस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है।

दूसरी ओर नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में जंतर-मंतर पर कॉकरोज जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से भी अनशन पर अड़े हैं। इस बीच गुरुवार सुबह-सुबह पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के मामलों की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है।

इधर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़प हो चुकी है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दिल्ली से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पटना, मुंबई जैसे शहरों में भी पहुंच चुका है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, मैं आज आपसे विनती करुंगा कि सरकार आगे आए, बयान दे और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. क्योंकि लाखों लोग सड़कों पर परेशान हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और कई लोग अस्पतालों में हैं, जबकि उनके माता-पिता परेशान हैं।

सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कहा, विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना है। ये न तो चर्चा करना चाहते हैं और न ही सदन को चलने देना चाहते हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित कर दी गई है। 12 बजे लोकसभा में दूसरी बार संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद हंगामा और नारेबाजी होती रही। जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर के 12 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।

विपक्ष चर्चा से भाग रहा है : रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि बिना शर्त चर्चा के लिए तैयार है, युवाओं के भविष्य के साथ विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदार है, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि चर्चा करें, लेकिन विपक्ष सिर्फ माहौल बना रहा ह, दूसरी ओर राज्यसभा में फिर से हंगामा होने के कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा में भी नारेबाजी और हंगामा जारी है।

शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में हादसा चार मजदूर घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। महानगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में एक बड़ा हादसा हुआ है। वहां पर प्लास्टर का काम कर रहे मजदूरों के गिरने की खबर है। हादसे में 4 मजदूर घायल हुए हैं। सूचना पर मौके पर महानगर पुलिस, तहसीलदार सदर और सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

तहसीलदार सदर जय प्रकाश ने बताया कि लोहे का बाड़ा टूटने से घटना हुई। जिसमें अभी तक चार लोग के घायल होने की सूचना मिली उनको अस्पताल भेजा गया है। शालीमार गैलेंट वेस्ट में मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है। घटना पर पहुंचे कुछ अधिकारी अंदर से निकले के बाद मुंह छिपा कर भागते नज़र आए। घायल चारों मजदूर समस्ती पुर बिहार के निवासी हैं।

राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम को 'सुप्रीम' झटका

» सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आरोपी ज़मानत की हकदार नहीं दोबारा जेल जाना पड़ेगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मेघालय के हनीमून मर्डर केस की आरोपी सोनम को दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम की जमानत रद्द करते नए कोर्ट ने माना है कि वह ज़मानत की हकदार नहीं है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी के समय सोनम को उसका कारण पता था। अगर अरेस्ट मेमो में टाइपिंग की कोई कमी थी, तो यह ज़मानत का आधार नहीं हो सकता। मुकदमा अभी अहमआचरण में है। अगर यह धीमी रफ्तार से चलता है और 6 महीने में पूरा नहीं होता तो वह ज़मानत का नया आवेदन दाखिल कर सकती है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 025 को सोनम से हुई थी। दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए। वहां चेरापूंजी में राजा लापता हो गए। बाद में उनकी लाश एक गहरी खाई से बरामद हुई। पुलिस ने जांच के बाद सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और दूसरे सहयोगियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया 9 जून 25 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय लापरवाही से तैयार किया गया अरेस्ट मेमो सोनम की ज़मानत का आधार बन गया। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय पुलिस का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने कहा कि सोनम लंबे समय तक फरार रही।

मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सीजेआई सख्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने आग्रह किया की कि कम से कम उन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मुद्दा उठाते हुए विकास सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के वैध पास हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा, मेट्रो में एक फायदा है कि जब वे ट्रेन से बाहर आते हैं तो वहां एक निकास बिंदु होता है। वहां उनकी जांच की जा सकती है। जिन लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है और बाकी लोगों से कहा जा सकता है कि वे दूसरी ट्रेन लें और चले जाएं। इससे लोग ट्रेन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही इस मामले को मेट्रो अधिकारियों के सामने उठाने के लिए कहा गया है।

» बोले- दोपहर तक समाधान नहीं हुआ तो करेंगे हस्तक्षेप

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि अगर यह मुद्दा नहीं सुलझता है तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे।सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, मैंने उन्हें सुबह ही इसकी जानकारी दे दी है। अब यह उनके ऊपर है कि वे अधिकारियों से बात करें। वह इसे समाधान के एक विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं।

दोपहर के भोजन तक अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है। अगर मेरे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केन्द्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह साढ़े सात बजे से अगले निर्देश तकबंद रखने का एलान किया।

महाराष्ट्र कार्यालय :- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार : मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा